Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278,
http://www.srjis.com/issues_data?issueId=211
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, APRIL-MAY 2023, VOL-11/57
https://doi.org/10.5281/zenodo.8185905

उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं का चलन: संभावनाएँ और चुनौंतियाँ

सविता आंदेलवार
अंग्रेजी विभाग राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदर सिंदरी, किशनगढ़, अजमेर. जि. राजस्थान
savitaganu@gmail.com

Paper Received On 20 May 2023
Peer Reviewed On 28 May 2023
Published On: 1 June 2023

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना: -

स्कूल स्तर के अध्ययन को आम तौर पर विकास की अवधि (Development Stage) कहा जाता है। इस दौरान छात्र को शिक्षा के माध्यम से संसार का परिचय दिया जाता है । इस परिचय में भाषाओं का ज्ञान भी शामिल है। छात्र को मातृभाषा के विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। और अन्य भाषाओं का समावेश किया जाता है। उच्च शिक्षा का क्षेत्र छात्र के जीवन में किसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना है। इस अवधि में छात्र जिनविषयों का अध्ययन करता है, वे एक प्रकार से उसकी आजीविका का साधन बनते हैं और असे विशेषज्ञता प्रदान करते है। इस कारण हम यह कह सकते है कि स्कूली स्तर पर भाषा का अध्ययन परिचय के लिए, सामान्य जानकारी के लिए किया जाता है, जबकि उच्च शिक्षा में उन्हें अधिक व्यावहारिक धरातल पर अपने जीवन के लिए तैयार किया जाता है।

भारत में त्रिभाषा सूत्र केवल स्कूली स्तर तक की शिक्षा के लिए अपनाई गई नीति है, क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि स्कूली स्तर पर छात्रों को अपनी भाषा के साथ-साथ किन्हीं और भाषाओं का ज्ञान देना शैक्षिक दृष्टि से

आवश्यक है, उपयोगी है। उच्च शिक्षा में भी छात्र को अपनी भाषा के साथ अन्य किन्हीं भाषाओं का अध्ययन करने का अवसर दिया जाता है। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की नीति नहीं अपनाई जाति बल्कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में अन्य विषयों के अध्ययन के संदर्भ में भाषा के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में भाषाओं को शामिल करना जरूरी हैं।

वर्ष 1964-66 में कोठारी आयोग ने अपनी मुख्य अनुशंसा में यह कहा था कि न केवल स्कूली शिक्षा, बल्कि उच्च शिक्षा भी अपनी भाषा में दी जानी चाहिए। यह बात संसद ने भी मानी थी और देश के बुद्धिजीवियों ने भी, परंतु धरातल पर स्थिति नहीं बदली। इन बीते वर्षों में लोक सेवाओं से लेकर तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ता गया और उनमें भारतीय भाषाएं निरंतर पिछड़ती गईं। पिछली सदी के आठवें दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रम हिंदी में संचालित होते थे, लेकिन आज स्थिति उलट है। भारत के बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय भाषाओं मे शिक्षा नही मिलती है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रादेशिक भाषाओं के चलन का जायजा इस शोध आलेख में प्रस्तुत किया गया है।

शोध आलेख के उद्देश:-

उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं को चलन बढ़ने से कुछ लाभ है और कुछ चुनौतिंया भी है। उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं चलन के लाभ को उजागर करना और चुनौतियों को स्पष्ट कर सुझाव प्रस्तुत करना इस शोध आलेख का प्रधान उद्देश है।

शोध पध्दती:-

यह शोध आलेख पूर्णत: द्वीतियक तथ्योंपर आधारित है। तथ्यों का संकलन करने हेतु कुछ संदर्भ ग्रंथ, शोध आलेख, प्रबंध, ऑनलाईन साहित्य

का सहारा लिया गया है। इन स्त्रोतों से प्राप्त प्रदत्तो का निम्न प्रकार चिकित्सक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारत में उच्च शिक्षा का भाषा माध्यम-

वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरामन रामकृष्णन भारत आए थै। उन्होंने यह दोहराया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी उसका अंग्रेजी पर निर्भर रहना है। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना होगा। तभी वैज्ञानिक चेतना और शोध में रचनात्मकता आएगी। उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं का महत्व मद्देनजर रखते हुवे भारते गृह मंत्री द्वारा इंजीनियरिंग, कानून और चिकित्सा को भारतीय भाषाओं में पढ़ाये जाने का आह्वान एक नेक इरादे से किया गया है। एनईपी द्विभाषी कार्यक्रमों की पेशकश के अलावा, उच्च शिक्षा संस्थानों और उच्च शिक्षा में कार्यक्रमों को शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए प्रदान करता है। इस आह्वान के पीछे तर्क यह है कि 95% छात्र, जो अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें उच्च अध्ययन के क्षेत्र में पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

भारत में हाल के वर्षों में, प्रादेशिक भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपाय किए गए हैं। 2021-22 से प्रभावी, एआईसीटीई ने 10 राज्यों में 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों को छह भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई है। परिषद ने एक "एआईसीटीई ट्रांसलेशन ऑटोमेशन एआई टूल" भी विकसित किया है जो अंग्रेजी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का 12 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। इसका सभी वर्गों को उच्च शिक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लाभ-

1) बेहतर आकलन :

मातृभाषा सीखने के लिए किसी पाठशाला की जरुरत नहीं होती। मातृभाषा व्यक्ती को स्वत: ही अपने परिजनों द्वारा उपहार स्वरुप मिलती है। जन्म लेने के बाद मानव प्रथम अपनी भाषा सीखता है। यह देखा गया है कि मानव मन जिस भाषा में बचपन से ही सोचने का आदी होता है, उसी भाषा में संचार के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है। शोध बताते हैं कि लोगों की सोच और भावनाओं को तैयार करने में मातृभाषा महत्वपूर्ण है। अपनी भाषा में सीखने से छात्र को स्वयं को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने में मदद मिलेगी।

2) सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि:

भारत में बडे विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध नही हैं। इसी कारणवश मातृभाषा में बोलने वाले छात्रों की संख्या ऐसे संस्थानों में न के बराबर है। यदी इन संस्थानों में मातृभाषा या भारतीय भाषाओं में अध्ययन के अवसद प्रदान किए गए तो शिक्षा का अवसर यह अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा और इस प्रकार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) में वृद्धि करेगा।

3) स्कूल छोड़ने की दर कम करना:

भारत में अभीतक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में बहुतही कम अवसर उपलब्ध थे। इसी कारण गाव से आए छात्र को उच्च शिक्षा लेने में कठिनाईंया आती थी। इन छात्रों में बीच में स्कूल या उच्च शिक्षा छोडने की प्रवृत्ती अधिक पाई जाती थी। पर उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं का चलन बढनेसे विषय को समझने से छात्र का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसे अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा और इस प्रकार

ड्रॉप-आउट दर को कम करेगा। भारतीय भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता, सर सी.वी. रमन के अनुसार, "हमें अपनी मातृभाषा में विज्ञान पढ़ाना चाहिए। अन्यथा, विज्ञान एक हाईब्रो गतिविधि बन जाएगा। यह ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिसमें सभी लोग भाग ले सकें।"

4) समान शिक्षा संस्कृति:

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता पाई जाती है। जीन छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिती अच्छी है, वह ढेर सारा स्कूल का शुल्क भरके अच्छी इंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मगर सामान्य सामाजिक आर्थिक स्थिती के छात्र ऐसी महंगी शिक्षा नहीं ले सकते है। इसी कारण उच्च शिक्षा में मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिलने से एक समान शिक्षा प्रणाली निर्माण में मदद मिलेगी। छात्रों की व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ किसी भी तरह से उनकी पूर्ण शैक्षणिक क्षमता को साकार करने में बाधा नहीं होनी चाहिए।

5) संस्कृति को संरक्षित करता है:

अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा में सीखना भी अपनी संस्कृति और विरासत से अलगाव की भावना लाता है। मातृभाषा में शिक्षा छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। और इसलिए, उसकी जड़ों को बरकरार रखते हुए उसे जीवन में प्रगति में मदद करता है।

6) वैश्विक प्रथाएं:

आज विश्व के G20 के अधिकांश देशों में अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हैं, जहां उनके लोगों की प्रमुख भाषा में शिक्षण दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में, लगभग 70% विश्वविद्यालय कोरियाई में पढ़ाते हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय मंच

पर भूमिका निभाने की इच्छा रखते हों। यह प्रवृत्ति चीन, जापान और कनाडा जैसे अन्य देशों में भी देखी जाती है। ऐसे में भारत में प्रादेशिक भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना गैर नहीं होगा।

क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में चुनौतियां-

1) क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का अभाव:

भारत में इंजिनिअरिंग और मेडिकल जैसे पाठ्यक्रमों में प्रादेशिक भाषाओं में अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। विशेष रूप से तकनीकी पाठ्यक्रमों में अधिक छात्रों के लिए देशी भाषाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों की कमी है। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में बाधा निर्माण हो सकती है।

2) अनुवादों की विश्वसनीयता:

आज मेडिकल, तकनीकी पाठ्यक्रमों पर अंग्रेजी भाषा में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों, अकादमिक पत्रिकाओं और वीडियो का अनुवाद करने के लिए कृत्रिम बुद्धि-संचालित उपकरण इन अनुवादों की गुणवत्ता के साथ विश्वसनीयता और अनियमितताओं के मुद्दे पैदा कर सकते हैं। इस कारण भी क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में बाधा निर्माण हो सकती है।

3) कुशल शिक्षण कर्मचारी:

क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय माध्यम में कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। भारत में उच्च शिक्षा की अंग्रेजी-माध्यम की विरासत को देखते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को आकर्षित करना और बनाए रखना जो क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने के इच्छुक और सक्षम हैं, एक चुनौती होगी।

Copyright@2023 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

4) रोजगारपरकता:

उच्च शिक्षा लेने का मकसद रोजगार प्राप्ती भी है। कॉलेज में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की पहले से ही दयनीय रोजगार योग्यता को देखते हुए, एक क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन करने से नौकरी के अवसर और बाधित हो सकते हैं, भारत के भाषा विभाजन को तेज कर सकते हैं और वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों में विश्वास पैदा करने के लक्ष्य के खिलाफ जा सकते हैं।

5) वैश्विक श्रम के साथ प्रतिस्पर्धा:

उच्च शिक्षा संस्थाओं में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने से छात्रों को वैश्विक श्रम और शिक्षा बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने से रोका जा सकता है, जहां अंग्रेजी में प्रवाह एक अलग बढ़त देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छात्रों के लिए अवसरों की कमी अभिजात्य वर्ग और बाकी के बीच की खाई को पाटने के नीतिगत उद्देश्य के प्रतिकूल साबित हो सकती है।

निष्कर्ष:-

- भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों द्वारा राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप के बिना दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली पर चर्चा की जानी चाहिए।
- अंग्रेजी का उपयोग, जहां भी वांछनीय हो, बनाए रखा जाना चाहिए, इस आधार पर कोई घृणा नहीं दिखाई जानी चाहिए कि यह एक "विदेशी" भाषा है।
- स्कूलों में भारतीय भाषाओं के शिक्षण के मानकों और गुणवत्ता के मुद्दों को उजागर करना अनुचित नहीं होगा।

Copyright@2023 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

- आज तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में देशी भाषा के निर्देश के निहितार्थों को भारत के लिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

सार-

भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं को अपेक्षित महत्व देने की पहल की गई है। हालांकि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को लेकर कुछ चर्चा जरूरी है। जब इंजीनियरिंग और मेडिकल से लेकर समस्त उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्ता मिलेगी तभी न केवल लोक सेवाओं, बल्कि अन्य सरकारी एवं गैरसरकारी नौकरियों में भारतीय भाषी छात्रों के -प्रशासन -दिन सुधरेंगे। यह उनके लिए अवसर बढ़ाने के साथ ही देश के शासन के लिए भी आवश्यक है। इससे अंग्रेजी के आधिपत्य पर भी अंकुश लगेगा। साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद भी मजबूत हो सकेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन्होने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भारतीय भाषाओं में शिक्षण उपलब्ध कराने की घोषणा की है यह घोषणा यदि मूर्त रूप लेती है तो यह शिक्षा जगत के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।

संदर्भसूची-

सिंग, भूपेंद्र .*(2020)*. उच्च शि क्षा का आधार बनें भारतीय भाषाएं: आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति भारतीय भाषाओं से ही संभव. जागरन ब्लॉग, *https://www.jagran.com/editorial/apnibaat-indian-languages-should-be-base-of-higher-education-fulfillment-of-resolve-of-self-reliant-india-possible-only-with-indian-languages*-21141355.*html*

द हिंदू- भाषा बाधा: मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना- समसामायिकी लेख- *https://www.dhyeyaias.in/current-affairs/articles/language-barrier-making-mother-tongue-the-medium-of-higher-education*

अयाचित, आरती. *(2021)*. शिक्षा में भाषा का महत्व. *https://jmcstudyhub.com/importance-of-language-in-education/*

तिवारी, राघवेंद्र प्रसार. *(2022)*. उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को और बढ़ावा मिले. *https://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/nbtguestblog/indian-languages-should-be-promoted-in-higher-education/*

नई शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषाएं- *https://www.loknitikendra.com/new-education-policy-and-indian-languages/*

Cite Your Article As:

Savita Aandelvar. (2023). UCHH SHIKSHA MAI PRADESHIK BHASHAYO KA CHALAN: SAMBHAVNAYA AUR CHUNAUTIYA. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,, 11(57), 297–305. https://doi.org/10.5281/zenodo.8185905

Copyright@2023 Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language